

'One seat reserved for SC/ST on boards of co-op societies'



'One seat reserved for SC/ST on boards of co-op societies'

Union Cooperation Minister Amit Shah on Tuesday informed the Lok Sabha that two seats had been reserved for women, and one seat for Scheduled Castes (SC) or Scheduled Tribes (ST) on the boards of multi-State cooperative societies, while responding to Congress leader Rahul Gandhi's questions on initiatives to increase SC/ST participation.

Two seats in the boards of cooperative societies are reserved for women and one seat for scheduled castes and scheduled tribes: Shah

सहकारी समितियों के बोर्ड में दो सीट महिलाओं और एक सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित : शाह
सहकारिता मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के सवाल का लोकसभा में दिया जवाब, भागीदारी होगी सुनिश्चित

नई दिल्ली। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अब बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो व अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित की गई है। यह कदम सहकारी क्षेत्र में समावेशिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

शाह ने कहा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के मॉडल उप-नियमों में भी यही प्रावधान शामिल



कर राज्यों को भेजे गए हैं, ताकि महिलाओं और एससी/एसटी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो। कांग्रेस सांसद राहुल ने सहकारी समितियों में एससी/एसटी की भागीदारी बढ़ाने के

चीनी मिलों के लिए 1,000 करोड़ का अनुदान

शाह ने कहा, सहकारी चीनी मिलों की मजबूती के लिए सरकार ने एनसीडीसी को 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया। इसके जरिए उसने बाजार से अतिरिक्त उधार लेकर कुल 10,000 करोड़ की मदद उपलब्ध कराई। यह राशि इथेनॉल प्लांट, को-जनरेशन प्लांट व पूंजी जरूरतों को पूरा करने में लगाई जा रही है। अब तक 109 ऋण मंजूर किए गए हैं, जिससे 56 सहकारी चीनी मिलों को सीधा लाभ हुआ है।

उपायों व मंत्रालय की योजनाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधानों पर जानकारी मांगी थी। शाह ने कहा, मंत्रालय कई योजनाएं चला रहा है, जिनमें पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, राष्ट्रीय सहकारी

विकास निगम (एनसीडीसी) को अनुदान व आईटी हस्तक्षेप शामिल हैं। इनसे सहकारी समितियों के सदस्य लाभान्वित होते हैं, जिनमें एससी/एसटी किसान भी शामिल हैं।

Complaint box and biometric system started in RCS

आरसीएस में शिकायत पेटी और बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने मंगलवार को आरसीएस (रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज दिल्ली) कार्यालय में जनसुनवाई की। कार्यालय परिसर में लगाई गई शिकायत पेटी, बायोमेट्रिक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों का शुभारंभ किया।

मंत्री ने कहा कि इससे शिकायतों के तेजी से समाधान में मदद मिलेगी। रविन्द्र इंद्राज ने कहा कि

सहकारिता मंत्री ने आरसीएस कार्यालय में की जनसुनवाई शिकायतों को गंभीरता से लें

इस साल अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है, इसलिए जनहित में लगातार नई पहल शुरू की जाए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के संकल्प सहकारिता से समृद्धि की दिशा में दिल्ली भी लक्ष्य बनाए। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका समय से निस्तारण हो।

'Sahakar Taxi' service will start in Delhi

दिल्ली में शुरू होगी 'सहकार टैक्सी' सेवा

अरविंद शर्मा • जागरण

नई दिल्ली : केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र में नई पहल करते हुए ओला-उबर की तर्ज पर सहकार टैक्सी सेवा की शुरुआत करने जा रही है। यह चालक और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभदायक होगी। इसकी शुरुआत दिल्ली और गुजरात से की जा रही है। बाद में देशभर में जिलास्तर तक ले जाने की योजना है। सहकारिता मंत्रालय ने इसके लिए को-ऑपरेटिव लिमिटेड का गठन कर दिया है। एप बनाने का काम जारी है।

टैक्सी चालकों को अधिक फायदा: अभी टैक्सी चालकों को अपनी कमाई का 20 से 30 प्रतिशत कमीशन के रूप में कंपनियों को देना पड़ता है। सहकारी माडल में उनकी लगभग पूरी कमाई उन्हीं की होगी। कमीशन नहीं कटने से हर राइड पर अधिक आय होगी। उपभोक्ता के बिल में भी कमी आएगी। पिछले

- दिल्ली और गुजरात से होगी शुरुआत, बाद में सभी बड़े शहरों में शुरू की जाएगी सेवा
- एप बनाने का काम जारी, जिला स्तर तक ले जाने की योजना, चालक व उपभोक्ता दोनों को लाभ



वर्षों में देखा गया है कि ओला-उबर इस कमीशन के कारण ही सिर्फ अपने मनमाने रूट पर ही चलना चाहते हैं।

चालकों की होगी सीधी भागीदारी: सहकारी समिति में चालक सदस्य की तरह शामिल होंगे। इसलिए नियम, किराया और शर्तें तय करने में उनकी सीधी भागीदारी होगी। उन्हें मनमाने जुर्माने और अकाउंट

यात्रियों को मिलेगा फायदा

यात्रियों की शिकायतों का निवारण जल्दी होगा, क्योंकि ड्राइवर और संस्था दोनों स्थानीय होंगे। सहकारी संस्था होने से यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा कि यह किसी मुनाफाखोर कंपनी की सेवा नहीं है। उन्हें यह संतोष होगा कि उनका पैसा सीधे चालक की जेब में जा रहा है, किसी बिचौलिये के पास नहीं। चालक स्वयं मालिक होने के कारण यात्रियों के साथ बेहतर व्यवहार रखने का प्रयास करेंगे।

ब्लाक जैसी समस्याओं से भी राहत मिलेगी। समिति की नियमावली में चालकों को सुरक्षा बीमा, लोन और अन्य सुविधाएं देने का प्रविधान है। सहकार टैक्सी सेवा में किराया नियम स्पष्ट और पारदर्शी होंगे। सहकारिता को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों से चालकों को लाइसेंस और सरकार की ओर से वित्तीय मदद भी आसानी से मिल सकेगी।

Five times increase in milk procurement: Shah

दूध खरीद में पांच गुणा बढ़ौतरी : शाह

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि गुजरात में दूध की खरीद 2001-02 में 50 लाख लीटर प्रतिदिन से पांच गुना बढ़कर 2024-25 में 250 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि डेरी किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पिछले 15 वर्षों में किसानों को दिए जाने वाले दूध के मूल्य में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (औसत दूध खरीद मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम वसा से बढ़कर 950 रुपये प्रति किलोग्राम वसा हो गया है)।

शाह ने बताया कि इससे दुग्ध संघों की शीतलन क्षमता और दूध खरीद क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) और पशुपालन



● इससे दुग्ध संघों की शीतलन क्षमता और दूध खरीद क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली है

अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) जैसी योजनाओं ने अवसंरचना आधुनिकीकरण, मूल्य संवर्धन सुविधाओं, (पशु) नस्ल सुधार और चारा विकास के लिए सहायता प्रदान की है।

पिछले सात वर्षों में, एनपीडीडी के तहत गुजरात को 515 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय के साथ 315 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

बोर्ड में महिलाओं के लिए 2, एससी-एसटी के लिए 1 सीट

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद को बताया कि एक से अधिक राज्य में संचालित होने वाली सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीट और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए एक सीट आरक्षित की गई है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सहकारिता क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। शाह ने बताया कि सरकार ने सभी राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए आदर्श उप-नियमों में इसी तरह के प्रावधान शामिल किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पैक्स की सदस्यता को और अधिक समावेशी बनाना है।

RCS related complaints should be resolved with transparency: Indraj

पारदर्शिता के साथ हो आरसीएस से जुड़ी शिकायतों का निवारण : इंद्राज

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज (आरसीएस) के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा अब बायोमेट्रिक प्रणाली एवं सीसीटीवी की निगरानी में होगा। इसके लिए कार्यालय परिसर में शिकायत पेटिका और सीसीटीवी लगाए गए हैं। समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया। लंबित शिकायतों का निपटारा करने के आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सीसीटीवी की निगरानी में समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह सुझावों के माध्यम से कार्यशैली को बेहतर बनाएं। जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने इस नई व्यवस्था का स्वागत करते हुए मंत्री का आभार जताया है। मंत्री ने कहा कि यह साल अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

■ कार्यालय परिसर में शिकायत पेटिका के साथ ही लगाए गए सीसीटीवी कैमरे

है, जनहित में शुरू की गई इस पहल को सुविधानगर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के संकल्प के तहत सहकारिता से समृद्धि की दिशा में विभाग लक्ष्य निधारित करे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में विभागीय योजनाओं को तैयार करते समय 'सहकारिता से आत्मनिर्भरता' की मूल भावना को केंद्र में रखा जाए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जन शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो। सहकारिता विभाग का उद्देश्य आमजन को पारदर्शी, जिम्मेदार और त्वरित सेवाएं मुहैया कराना है।